

उत्तराखण्ड शासन

सूचना एवं प्रिक्षान प्रीधोगिकी प्रिभाग- अनु०-०१
 संख्या:- ४७३ / श०४४-१ / २०२०-३१ / २०१४ टी०सी०-०१
 देहशादून, दिनांक: २१ सितम्बर, २०२०

कठिपद रामो
का राजीवन

अन्याय-४ का राजीवन

२.गूल नीति के अध्याय-४ की सारणी आई०टी० प्रिभाग द्वारा, अंतिरिक्ष प्रितीय प्रोत्साहन में नवा उभारक-७ निम्नलृत अन्तर्लापित कर दिया जायेगा; अर्थात्:-

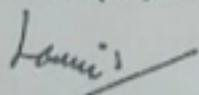
उत्तराखण्ड सूचना प्रीधोगिकी नीति, २०१८, (जिसे यहाँ आगे गूल नीति कहा गया है) में-

(१) जहाँ-जहाँ शब्द "सूचना प्रीधोगिकी प्रिभाग" आये हैं को स्थान पर शब्द "सूचना एवं प्रिक्षान प्रीधोगिकी प्रिभाग" रख दिये जायेंगे।

७. उत्तराखण्ड के चुनून देशी एवं ढार्क ग्रामों में दूरसंचार और ब्राउज़ेर मुदिया प्रदान करने हेतु कुल पूँजीगत व्यय (Capital Expenditure-CAPEX) पर ३०% या रु५०० लाख. जो भी कम हो, की अनुदान/प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। परिदौजना प्रस्ताव को राज्य के सूचना एवं प्रिक्षान प्रीधोगिकी प्रिभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

संगठन/कांपनी/कर्म, इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई०एस०पी०) एवं दूरसंचार सेवा प्रदाता (टी०एस०पी०) जो अनुदान/प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं, वह अन्य संगठन/कांपनी/कर्म, इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई०एस०पी०) एवं दूरसंचार सेवा प्रदाता (टी०एस०पी०), जो भविष्य में यह सेवा प्रदान करते का इरादा रखते हैं और जिनके प्रस्ताव सूचना एवं प्रिक्षान प्रीधोगिकी प्रिभाग द्वारा अनुमोदित है, के साथ वापरस्थापना दोषे को साझा करने के लिए बात्य होगे। संगठन/कांपनी/कर्म, इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई०एस०पी०) एवं दूरसंचार सेवा प्रदाता (टी०एस०पी०) पूँजीगत व्यय (CAPEX) को अनुपात में आपस में बांट सकते हैं।

परिशिष्ट "क" का राजीवन ३. मूल नीति के परिशिष्ट "क" के उभारक-१३ ए में नई प्रविधि जोलह निम्नादत अन्तर्लापित कर दी जायेगी, अर्थात्:-
 (१६) इंटरनेट सेवा प्रदाता (आई०एस०पी०) एवं दूरसंचार सेवा प्रदाता (टी०एस०पी०)


 ✓ (रमेश कुमार सुधांशु)
 संचित।

Government of Uttarakhand
Department of Information and Science Technology (Sec-01)
No.- 611 /XXXXV-1/2020-31/2014 TC-01
Dehradun, Dated: 1st September, 2020

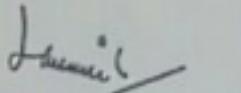
Amendments 1. In the Information Technology Policy 2018 (hereinafter referred as the Principal Policy)-
of certain words
Wherever the words 'Information Technology Department' occur, the word 'Department of Information and Science Technology "shall" be substituted.

Amendment of Chapter 4 - 2.
2. In principal policy In "additional fiscal incentives by IT department" table of chapter-4 new serial no-7 shall be inserted as follows, namely:-

7. Subsidy/incentive for providing Telecommunication and/ or Broadband in Remote areas and dark villages of Uttarakhand. A total subsidy/incentive of 30% of Rs.50 lakhs whichever is lower, on the total Capital Expenditure (CAPEX), shall be allowed as subsidy for providing Telecommunication and/ or Broadband in Remote areas and dark villages of Uttarakhand. Project proposal shall be approved by State Information and Science Technology Department.

Organizations/Companies/Firms (Internet Service Providers (ISP)), and Telecommunication Service Providers(TSP)), that seek above subsidy shall be bound to share the Infrastructure with other Organizations/Companies/Firms who also intend to provide Internet Services / Telecommunication Services in that area on a subsequent date and whose proposal has been approved by State Information and Science Technology Department. The Organizations, Companies / Firms may share the Capital Expenditure (CAPEX) cost amongst themselves as a ratio.

Amendment of Annexure "A" 3. In the Principal Policy Is serial No-13 C of Annexure "A" new entry (XVI) shall be inserted as follows, namely:-
(xvi) Internet Service Providers(ISP) and Telecommunication Service Providers(TSP)


✓ (Ramesh Kumar Sudhanshu)
Secretary